इंटरनेशनल रिसर्च सैंटर के वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक का आयोजन हुआ।

18. कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015' में किसानों के कल्याण के लिए कृषक संगठनों की भूमिका पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।
19. कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2015।
20. दिनांक 1 फरवरी 2016 को सीआईआरबी, हिसार में भैंस मेले का संस्थान के साथ मिलकर आयोजन किया गया।
21. दिनांक 9 जून 2016 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक का आयोजन।
22. दिनांक 27 जून 2016 को 'हरियाणा के परिनगरीय क्षेत्रों में कृषि का विविधीकरण' विषय पर कार्यदल की बैठक।
23. दिनांक 9–11 जुलाई 2016 को 'हरियाणा में मधुमक्खी पालन के प्रवर्धन' पर कार्यदल की बैठक।
24. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 13 जुलाई 2016 को हरियाणा बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ 'हरियाणा में परिनगरीय क्षेत्रों में कृषि का विविधीकरण' विषय पर कार्यदल की बैठक।
25. दिनांक 25–26 जुलाई 2016 को 'हरियाणा में मधुमक्खी पालन का प्रवर्धन' विषय पर कार्यदल की बैठक।
26. दिनांक 5 अगस्त 2016 को हिसार में 'हरियाणा में दुधारू गौपशुओं और भैंसों से संबंधित पशु पोषण' पर कार्य दल की बैठक।
27. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ 8 अगस्त 2016 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 'हरियाणा में कृषि विस्तार' पर विचार–मंथन सत्र।

किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

1. एनडीआरआई, करनाल में 9 सितम्बर 2010 को डेरी किसानों के साथ बैठक।
2. सीएसएसआरआई, करनाल में 8 अक्तूबर 2010 को किसानों के साथ बैठक।
3. राज्य में प्रत्येक प्रशासनिक प्रभाग के किसानों के साथ चार परामर्श बैठकें।
4. हिसार में 3 अप्रैल 2011 को राज्य के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठकों का आयोजन।
5. दिनांक 17 मई 2011 को मेवात किसान क्लब के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन।
6. दिनांक 24 जून 2011 को नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ के किसानों के साथ बैठक का आयोजन।
7. एनडीआरआई करनाल में 23 सितम्बर 2011 को हरियाणा के मछली पालन किसानों के साथ परिचर्चा बैठक का आयोजन हुआ।
8. दिनांक 12 अक्तूबर 2011 को पंजाब के डेरी किसानों के साथ परिचर्चा बैठक।
9. चंडीगढ़ में 13 अक्तूबर 2011 को पंजाब के पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ परिचर्चा बैठक।
10. दिनांक 17 अक्तूबर 2011 को बल्लभगढ़ के प्रगतिशील किसानों के साथ परिचर्चा बैठक आयोजित हुई।
11. हिसार में 25 फरवरी 2012 को राज्य के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
12. पानीपत में 09 जून 2012 को रोहतक प्रभाग के प्रगतिशील किसानों के साथ परिचर्चा बैठक का आयोजन।
13. सीएसएसआरआई, करनाल में 20 मई 2013 को 'मक्का के माध्यम से ऊर्जावान विविधीकरण विकल्प व जलवायु – स्मार्ट विधियों को बढ़ावा देने' पर स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श।
14. एनडीआरआई, करनाल में 31 मई 2013 को दूध की मूल्य निर्धारण नीति पर विशेषज्ञ परामर्श बैठक।
15. दिनांक 5 जून 2013 को हरियाणा में सुरक्षित खेती करने वाले किसानों के साथ एक परिचर्चा का आयोजन।
16. दिनांक 8 जनवरी 2014 को गोपशु विकास पर स्टेकहोल्डर बैठक।
17. दिनांक 7 मार्च 2014 और 30 जून 2014 को कपास में आईपीएम पर कार्य करने वाली जींद जिले की महिला किसानों के साथ बैठक का आयोजन।
18. बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, उचानी, करनाल में 16 जनवरी 2015 को मधुमक्खी पालकों के साथ एक परिचर्चा बैठक का आयोजन।
19. दिनांक 16 अप्रैल 2015 को सेवा (सैल्फ एम्प्लॉइड वीमेन एसोसिएशन), गुजरात से महिला किसानों के चार अध्ययन दौरे हरियाण किसान आयोग द्वारा आयोजित किए गए।
20. किसान भवन, पंचकुला में 18 मई 2015 को सेना अधिकारियों तथा पूर्व सैनिकों के साथ बैठक।
21. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 19 नवम्बर 2015 को जिला किसान क्लबों के अध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन।
22. दिनांक 10 दिसम्बर 2015 को आईपीएम पर कार्य करने वाले जींद जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक का आयोजन।

हरियाणा किसान आयोग को सरकारी सहायता

हरियाणा किसान आयोग सरकार को इस तथ्य पर सहमत करने में सफल रहा है कि फार्म से जुड़ी नई–नई खोजों या नवोन्मेषों को अनुकूल बनाना तथा वर्तमान अनुसंधान में जो अंतराल हैं उन्हें पाटना खेती से होने वाली आय को बढ़ाने, कृषि में टिकाऊपन लाने और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तदनुसार राज्य सरकार हरियाणा किसान आयोग के सुझावों पर सहमत है और निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराई है।

- कृषि नवोन्मेष निधि

किसानों द्वारा किए गए नवोन्मेषों को पहचानने व उन्हें वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में अनुकूल बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

- हरियाणा राज्य कृषि अनुसंधान एवं विकास निधि

सरकार ने अनुसंधान में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए 6 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसका लाभ उठाने के लिए हरियाणा में स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और भा.कृ.अ.प. के संस्थानों; राज्य कृषि विभागों, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी आदि; और प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा परियोजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं।

हरियाणा किसान आयोग
अनाज मंडी, सेक्टर 20
पंचकूला – 134116
टेलिफोन: +91–172–2551764
फैक्स: +91–172–2551864
Website:- www.haryanakisanayog.org

हरियाणा किसान आयोग

एक झलक

।। बदलता हरियाणा – बढ़ता हरियाणा ।।

राज्य के किसानों की सेवा में प्रगामी कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई, 2010 को हरियाणा किसान आयोग का गठन किया। इसका मुख्यालय अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला में है।

हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार यादव है तथा इसके सदस्य डॉ. श्याम भास्कर, डॉ. राजेन्द्र सिंह बाल्यान, डॉ. अभिलक्ष लिखी (आईएएस) प्रधान सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार और डॉ. के.पी. सिंह, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार है। जबकि डॉ. आर.एस. दलाल, सदस्य–सचिव हैं।

मुख्य उद्देश्य

1. हरियाणा कृषि, इसके निष्पादन, इसकी शक्तियों और निर्बलताओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की दशाओं का मूल्यांकन करना तथा राज्य में टिकाऊ और समान कृषि विकास प्राप्त करने के लिए वृहत कार्यनीतियां तैयार करना।
2. खेती से होने वाली आय में आने वाली गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करना और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
3. राज्य की प्रमुख फार्मिंग प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, टिकाऊपन और स्थिरता को बढ़ाने की विधियां प्रस्तावित करना।
4. व्यावहारिक और सक्षम फसल (बागवानी सहित) – पशुधन, मछली समेकित प्रणाली के लिए सुझाव देना तथा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना।
5. बीजों, नाशकजीवनाशियों और ऋण की प्रदानीकरण प्रणालियों की कार्यविधि के साथ–साथ निवेश उपयोग की वर्तमान दक्षता की जांच करना तथा इनमें सुधार के उपाय सुझाना।
6. कृषि में जल के उपयोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और इसकी दक्षता में सुधार के उपाय सुझाना।

सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टें

आयोग द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विभिन्न तकनीकी कार्यदल गठित किए गए हैं। इन्होंने किसानो, वैज्ञानिको एवं सलाहकारों से गहन चर्चा के उपरांत अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ऐसी अपेक्षा है कि इन रिपोर्टों से कृषि को ऊर्जावान और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने की दृष्टि से कार्यनीतिपरक योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी। किसान आयोग अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर चुका है।

1. हरियाणा राज्य कृषि नीति का मसौदा
2. किसानों से हुई परिचर्चा पर आधारित पर नीतिगत बिन्दुओं व विकल्पों पर रिपोर्ट
3. हरियाणा में कृषि अनुसंधान वं विकास के लिए मुद्दों और विकल्पों पर रिपोर्ट
4. हरियाणा में टिकाऊ फसलोउत्पादन के लिए संरक्षित कृषि पर रिपोर्ट
5. हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर रिपोर्ट
6. हरियाणा में मात्स्यिकी विकास स्थिति, सम्भावनाएं एंव विकल्प पर रिपोर्ट
7. हरियाणा में बागवानी विकास पर रिपोर्ट
8. हरियाणा में संरक्षित कृषि पर रिपोर्ट
9. हरियाणा में पशुपालन विकास पर रिपोर्ट
10. हरियाणा में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर रिपोर्ट
11. हरियाणा में बारानी क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट
12. हरियाणा में किसानों का बाजार से सम्पर्क पर रिपोर्ट
13. हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यसंवर्धन पर रिपोर्ट

वर्तमान में कार्यरत तकनीकी कार्यदल

निम्न चार तकनीकी कार्य दल इस समय कार्यरत हैं। ये कार्यदल किसानों, वैज्ञानिकों तथा फील्ड अधिकारियों के साथ चर्चाएं व बैठक आयोजित कर रहे हैं तथा इनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं :

1. हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा हेतु कार्यदल
2. हरियाणा में कृषि विस्तार
3. हरियाणा के परिनगरीय क्षेत्रों में कृषि का विविधीकरण पर कार्यदल
4. हरियाणा में दुधारू गोपशुओं व भैंसों से संबंधित पशु पोषण पर कार्यदल

प्रस्तावित कार्य दल

1. हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा
2. हरियाणा में खुम्बी उत्पादन को बढ़ावा
3. कृषि में युवाओं व महिलाओं का सशक्तीकरण
4. निवेश उपयोग और आपूर्ति (बीज, जैवउर्वरक, उर्वरक, जैवनाशकजीवनाशी, नाशकजीवनाशी)
5. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का अभिमुखन
6. कृषि ऋण, सहकारिता एवं फसल बीमा

हरियाणा की टिकाऊ भूमि उपयोग योजना

हरियाणा किसान आयोग ने हरसैक, हिसार के सहयोग से कृषि के टिकाऊ विकास के लिए एक विस्तृत भूमि उपयोग की योजना बनाई है।

हरसैक ने यह परियोजना सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए हरियाणा किसान आयोग को पेश कर दी है। हरसैक ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए भूमि उपयोग की योजना बनाई है। इस परियोजना रिपोर्ट में हरियाणा में कृषि के विकास के लिए टिकाऊ भूमि उपयोग हेतु ब्लॉक विशिष्ट अनुशंसाएं सुझाई गई हैं। परियोजना द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य में कृषि के सकल विकास के लिए कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा लागू किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. कृषि ऋण पर ब्याज की दरें घटाकर 4 प्रतिशत की गई हैं।
2. खेती के लिए ऋण लेने पर स्टैम्प ड्यूटी हटा दी गई है।
3. लगभग सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
4. लगभग सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी कर दिए गए हैं।
5. राज्य पशुधन मिशन का शुभारंभ हो गया है।
6. मछली तालाबों के लिए जल की दरें बहुत कम कर दी गई हैं।
7. चावल–गेहूं प्रणाली में विविधीकरण को बढ़ावा देने और चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
8. चारा बीजोत्पादन के लिए रोलिंग प्लान तैयार किया जा रहा है।
9. एपीएमसी अधिनियम से फलो और सब्जियों को हटाए जाने के लिए सुधार लाए जा रहे है।
10. सब्जियों और फलों पर मंडी शुल्क माफ किया गया।
11. एडीओ के वेतनमान संशोधित किए गए हैं।

राज्य स्तर की कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन

आयोग ने स्टेकहोल्डरों की समस्याओं को जानने के लिए राज्य स्तर की निम्न कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा उनके कार्यवृत्त प्रकाशित किए हैं :

1. किसान जनित नवप्रवर्तनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला
2. कृषि में विविधीकरण के माध्यम से सम्पन्नता पर
3. मत्सय पालन पर राज्य स्तरीय मेला
4. कृषि में युवाओं के लिए अवसर
5. हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला
6. हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्धन पर कार्यशाला
7. खुम्बी की खेती पर राज्य स्तर का सेमिनार
8. हरियाणा के टिकाऊ भूमि उपयोग नियोजन पर कार्यशाला

किसानों, नीतिकारों और वैज्ञानिकों के साथ परिचर्चा

किसानों की समस्याओं, आवश्यकताओं को समझने और उनके कौशल विकास के लिए हरियाणा किसान आयोग ने किसानों के साथ कार्यशालाएं तथा परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें किसानों, नीतिकारों व वैज्ञानिकों को विचार–विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं निम्नानुसार हैं :

कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों का आयोजन

1. हिसार में 7 मई 2011 को खेतिहर महिलाओं के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई।
2. दिनांक 30 जुलाई 2011 को हरियाणा में मात्स्यिकी विकास : चुनौतियां एवं अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई।
3. दिनांक 06 अगस्त 2011 को हरियाणा में संरक्षित कृषि पर एक कार्यशाला आयोजित हुई।
4. दिनांक 16–17 दिसम्बर 2011 को हरियाणा में बागवानी विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ।
5. दिनांक 30 अप्रैल 2012 को राज्य कृषि नीति के मसौदे पर विचार मंथन सत्र का आयोजन हुआ।
6. नई दिल्ली में 29 अगस्त 2012 को हरियाणा में मात्स्यिकी विकास : स्थिति, संभावनाएं और विकल्प पर एक विचार–मंथन सत्र का आयोजन हुआ।
7. करनाल जिले के तरावड़ी गांव में 28 सितम्बर 2012 को हरियाणा में जलवायु से संबंधित कृषि की स्मार्ट विधियों के लिए किसानों के सशक्तीकरण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
8. एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 6 दिसम्बर 2012 को बागवानी तथा सुरक्षित खेती पर विचार–मंथन सत्र का आयोजन हुआ।
9. एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2013 को पशुपालन पर विचार–मंथन सत्र का आयोजन हुआ।
10. दिनांक 6 जून 2013 को जैविक खेती पर एक कार्यशाला हुई।
11. एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 3–5 सितम्बर 2013 को 'फार्म नवोन्मेषों को अनुकूल बनाना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
12. एनडीआरआई, करनाल में 22 दिसम्बर 2012 को 'कृषि में विविधकरण के माध्यम से समृद्धि' विषय पर सेमिनार का आयोजन।
13. एचएएमईटीआई, जींद में 7 मार्च 2014 को कपास में समेकित नाशीजीव प्रबंध पर विचारोत्तजन सत्र का आयोजन।
14. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 9 जून 2014 को 'हरियाणा के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्धन' पर कार्यशाला का आयोजन।
15. डीएचआरएम, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 13 अगस्त 2014 को हरियाणा में कृषि विस्तार पर विचार–मंथन सत्र का आयोजन।
16. कृषि विभाग, हरियाणा और हरियाणा किसान आयोग ने 24 फरवरी 2015 को हरियाणा की किसान यूनियनों के सहयोग से हरियाणा में फसल बीमा और गोपशु संरक्षण पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया।
17. भारत के गंगा–यमुना के मैदानों में मिट्टी और पानी की समस्याओं के संबंध में एक व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए 17 दिसम्बर 2014 को कृषि विज्ञानों के लिए जापान